

पहले मुख्य समाचार।

- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधान सभा में प्रस्तुत किया राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट
- नौ लाख बारह हजार छह सौ छियानवे करोड़ पैंतीस लाख रुपये के कुल बजट से प्रदेश के चौतरफा विकास को मिलेगी गति, पूंजीगत व्यय, शिक्षा-स्वास्थ्य और कृषि पर प्रदेश सरकार का है विशेष ध्यान।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विकसित भारत- विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की पूर्ति में निर्णायक होगा यह बजट।
- मुख्यमंत्री ने की आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा, शांति व्यवस्था भंग करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देश।

\*\*\*\*\*

प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा और अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। नौ लाख बारह हजार छह सौ छियानवे करोड़ पैंतीस लाख रुपये का यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग बारह दशमलव नौ प्रतिशत अधिक है। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के सशक्तिकरण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर है। उन्होंने बताया कि वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे की सीमा तीन प्रतिशत निर्धारित की गई है।

**वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9: अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4: एवं 6: है। कृषि और संबंध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9: है।**

श्री खन्ना ने कहा कि बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा सड़क, एक्सप्रेसवे, बिजली, सिंचाई, शहरी विकास और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा इसमें खास ध्यान पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों के संतुलित विकास पर दिया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट में 43 हजार 565 करोड़ 33 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल की गयी हैं और चिकित्सा शिक्षा के लिए 14 हजार नौ सौ सतानबे करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

**14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 1,023 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 130 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है जो 2025-2026 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।**

बजट में आयुष सेवाओं के लिए लगभग दो हजार आठ सौ सड़सठ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिये लगभग 10 हजार आठ सौ अठ्ठासी करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, यह वर्ष 2025-2026 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। ग्राम्य विकास की योजनाओं के लिए लगभग 25 हजार पांच सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

**ग्राम विकास की योजनाओं के लिए लगभग 25,500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु क्रमशः 5,544 करोड़ एवं 4,580 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 को से लेकर वर्ष 2025-26 तक 36,56,000 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 36,37,000 आवास पूर्ण हो गए।**

\*\*\*\*\*

प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा, अवस्थापना, सड़क और सेतु निर्माण, ऊर्जा, आईटी सेक्टर और महिला बाल कल्याण तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट

**वर्ष 2026-27 के बजट में बेसिक शिक्षा के लिए 77 हजार 622 करोड़ रुपये और माध्यमिक शिक्षा के लिए 22 हजार 167 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 6 हजार 591 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने की रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27 हजार 103 करोड़ रुपये और एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं के लिए तीन हजार 822 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22 हजार 676 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। बजट में ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65 हजार 926 करोड़ रुपये, पी.एम. कुसुम सूर्यघर योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये और सड़कों और सेतु के निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए 34 हजार 468 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सुशील चन्द्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।**

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बजट प्रस्तुत करने के बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिये स्थगित रही। कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, जो आज भी जारी रहेगी। वहीं विधान परिषद में कल उपमुख्यमंत्री और नेता सदन केशव प्रसाद मोर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट प्रस्तुत किया।

\*\*\*\*\*

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राज्य सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे समावेशी, दूरदर्शी और जनोन्मुखी बजट बताया है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से राज्य को समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है।

उन्होंने कहा कि बजट का मुख्य विषय महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम युवाओं, समृद्ध किसानों और सभी के लिए रोजगार है। उन्होंने इस बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में मील का पत्थर बताया। प्रदेश के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह बजट विकास, विश्वास और समृद्धि की भावना से तैयार किया गया है और प्रदेश को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि यह बजट केवल लोक लुभावना है। इससे सर्व समाज का विकास नहीं होगा।

बजट को लेकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार मिश्रा ने कहा कि ये राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

**बुनियादी ढांचे पर 13: की बड़ी वृद्धि की गई है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों की बात है। साथ ही छात्रों के लिए स्कूटी जैसी योजना युवा ऊर्जा को पंख देने का कार्य करेगी।**

बरेली की रहने वाली कोमल ने बजट में महिला समर्थ योजना के तहत जिले को मिल्क प्रोड्यूसर यूनिट देने पर सरकार का आभार जताया।

\*\*\*\*\*

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक भवन में प्रदेश की कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने होली, महाशिवरात्रि और रमजान सहित विभिन्न पर्व एवं त्योहारों के दौरान शान्ति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 02 से 04 मार्च तक होली का पर्व मनाया जाएगा। शोभा यात्राओं में उपद्रवी तत्वों की घुसपैठ किसी भी स्थिति में न होने पाए। रंग में भंग डालने वालों, के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।

मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

\*\*\*\*\*